धारक हैं । इनके पास क्रमशः 30% और 20% शेयर हैं ।

संयंत्र और मशीनरी के ठीक प्रकार से अनुसरण न करने और आधुनिकीकरण के अभाव और इस्पात संयंत्रों द्वारा अपेक्षित उच्च मूल्य उत्पादों के उत्पादन में सक्षम न होने के कारण के. एफ. एस. डब्ल्यू. रुग्ण हो गई। इस कारण के. एफ. एस डब्ल्यू. न्यून मूल्य के भारी मात्रा और आंशिक रूप से माध्यम मूल्य के कुछ उत्पादों के अधिक टनभार का उत्पादन कर सका । विगत वर्षों में कम्पनी उत्पादन में कमी हुई है जिससे इसकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है । लगातार खराब कार्य-निष्पादन के कारण के. एफ. एस. डब्ल्यू. रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की शर्तों के अनुसार रुग्ण कम्पनी बन गई। इस समय यह मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) के पास है । बी. आई. एफ. आर. द्वारा कई बार सुनवाई हो चुकी है परन्तु बी. आई. एफ. आर. द्वारा अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

PURCHASE OF UNIFORM IN ROURKELA STEEL PLANT

3439. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of STEEL be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rourkela Steel Plant has floated tender for purchase of uniforms, and shoes for its employees in the past two months;

(b) whether the details of offers have been received by the RSP from both private and public sector;

(c) whether any Central Government Undertaking has also participated in the tender;

(d) if so, the details thereof; and

(e) what protection is being given to the Central Government Undertakings ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV) : (a) No, Sir. Tenders were however floated in the 1st quarter of 1993.

(b) and (c) Yes, Sir.

(d) M/s. Bharat Leather Corporation, a Central Govrenment Undertaking has participated in the tender for boots and shoes and their offer s under scrutiny by the plant.

(e) No special protection is provided to Central Government Undertaking in the purchase of boots and shoes.

इंजीनियरी सामान सहायता कोष (इंजीनियरी गुडस असिस्टेन्स फंड) की स्थापना

3440. डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

श्री राम जेठमलानी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में इंजीनियरी सामान के, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियरी सामान सहायता निधि की स्थापना की गयी है

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है, कि इस कोष के माध्यम से इंजीनियरी सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रति पूर्ति योजना के अन्तर्गत सहायता दी जाती है,

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त योजना के अन्तर्गत लगभग 450 करोड़ रुपए के दावे भुगतान हेतु लम्बित हैं, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस्पात पर लगाए जाने वाले उपकर की दरों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) इंजीनियरी माल निर्यात सहायता निधि (ई. जी. ई. ए. एफ.)

1981 में बनाई गई थी और यह एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित लोहे और इस्पात की निर्धारित किस्मों पर उपकर लगाकर बनाई गई है। इस निधि का उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना (आई. पी. आर. एस.) के अधीन निर्यात उत्पादन में उपयोग की जाने वाली इस्पात की कच्ची सामग्रियों के घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के बीच के अन्तर की इंजीनियरी माल के निर्यातकों को प्रतिपूर्ति के लिए किया जाता है।

(ग) दिनांक 6-12-1993 की स्थिति के अनुसार धन की कमी के कारण 324 करोड़ रुपए की राशि के आई. पी. आर. एस. दावे लम्बित हैं।

(घ) इस्पात पर उपकरों की दरों में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

APPOINTMENT OF CORRUPT OFFICERS IN VARIOUS COMPANIES UNDER MINISTRY OF STEEL

3441. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of STEEL be pleased to state :

(a) whether Government have examined the cases for appointment of those persons who were earlier identified as corrupt officers in various companies under his Ministry's jurisdiction;

(b) whether some of those appointed by the PSUs were earlier rejected for any board level appointment by the ACC; and

(c) if so, the reasons and the details for taking such people on the level of Chief General Manager in different PSUs ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV) : (a) to (c) The board level appointments in Public Sector Undertakings (PSUs) under the administrative control of Ministry of Steel are made on the recommendations of PESB and with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet only after vigilance clearance has been given. Appointments below board level are made by the PSUs themselves in accordance with their own rules and regulations.

SETTING UP OF CONSTITUENCY DIVISION ON SAIL

3442. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU :
SMT. ILA PANDA :

Will the Minister of STEEL be pleased to state whether it is a fact that Government SAIL have set up consultancy division on exporting expertise and service in steel making ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV) :Yes, Sir, Steel Authority of India Limited has set up a consultancy division on exporting expertise and services in steel making, since 1-11-1993.

PRICES OFHOT-ROLLED STEEL AND PRODUCTS

3443. SHRI CHIMANBHAI MEHTA :
SHRI SUBRAMANIAN SWAMY:
SHRIMATI MIRA DAS :
SHRI G. G. SWELL :

Will the Minister of STEEL be pleased o state :

(a) whether it is a fact that the prices of Hot-rolled steel and other products are kept so high that Indian consumer, who is much poorer almost pay double the price, if so, the reasons thereof;

(b) whether it is also a fact that SAIL takes advantage of its monopoly supplier position;

(c) if so, whether it is also a fact that decontrolled and deregulated steel market is nothing but is a monopoly controlled market;

(d) what is CIF value of imported steel and added taxes on that; and